

हरियाणा।राज्यविद्युतबोर्डबनामनियंत्रणप्राधिकारीएवंउप

श्रमआयुक्त, हरियाणा।एवंअन्य (डी. एस. तेवतिया, जे.)

मजिस्ट्रेटसंहिताकेतहतकार्यवाईकरनेकीदृष्टिसे।केवलइसतथ्यसेकिशिकायतकर्तनिअदालतमेंअपनीशिकायतपेशकरनेकेलिएए कवकीलकोनियुक्तकियाहै, नुकसाननहींपहुँचायाजासकता; क्योंकिजिसउद्देश्यकोप्राप्तकरनाचाहागयावहवहीथा।मजिस्ट्रेटकोतत्कालमामलेमेंशिकायतकर्ताकोउसकीजांचकेलिएजेलसेवु लानाचाहिएथा।वहशक्तिनिस्संदेहउसकेपासथी।इसप्रकार, मेरेविचारमें, ऐसीप्रक्रियाअपनानेमेंमजिस्ट्रेटकीविफलतासेउसकेआदेशमेंअनौचित्यकापताचलताहैऔरइससेन्यायकागर्भपातहोगयाहै।इस लिए, मुझेउक्तआदेशकोरद्दूकरनेमेंकोईविवादकनहींहै।

. (6) उपरोक्तकारणोंसे,

इसयाचिकाकोस्वीकारकियाजाताहैऔरविवादितआदेशकोरद्दूकरदियाजाताहै।विद्रानमजिस्ट्रेटकोनिर्देशितकियाजाताहैकिव हशिकायतपरपूर्व-निर्धारितटिप्पणियोंकेआलोकमेंऔरकानूनकेअनुसारआगेबढ़ें।शिकायतकर्ताकोअपनेवकीलकेमाध्यमसे 1 मार्च 1983 कोविद्रानमजिस्ट्रेटकेसमक्षउपस्थितहोनेकानिर्देशदियाजाताहै।

एन.के.एस.

डी. एस. तेवतियासेपहलेजे।

हरियाणाराज्यविद्युतबोर्ड,-याचिकाकर्ता

बनाम

नियंत्रणप्राधिकारीएवंउपश्रमआयुक्त,

हरियाणाऔरअन्य,-प्रतिवादी।

1976 कीसिविलरिट्याचिकासंख्या 49।

16 फरवरी 1983.

ग्रेच्युटीभुगतानअधिनियम (1972 का XXXIX)–धारा 1(3) (बी)–पंजाबदुकानेंऔरवाणिज्यिकप्रतिष्ठानअधिनियम (1958 का XV)–धारा 2(iv), (viii) और (xxv) और 3(बी)– ग्रेच्युटीअधिनियमकेप्रावधान -

क्याहरियाणाराज्यविद्युतबोर्डपरलागूहोतेहैं - स्थापनाअधिनियमकीधारा 3 (बी) -

क्याबोर्डकोउक्तअधिनियमसेबाहररखागयाहै।

मानागयाकिपंजाबदुकानेंऔरवाणिज्यिकप्रतिष्ठानअधिनियम, 1958 कीधारा 3

इसतथ्यकेबारेमेंअनिश्चितताकोदूरकरतीहैकिक्याकोईउपक्रमजोजनताकोविजलीयाप्रकाशकीआपूर्तिकरताहैवह 'प्रतिष्ठान' हैयानहीं।यदिइसअधिनियमकीधारा 3 नहींहोती, तोइसमेंप्रश्नगतपरिभाषाखंडकीव्याख्याशामिलहोती

आई.एल.आर. पंजाबऔरहरियाणा

यहतयकरेंकिक्यापरिभाषितअभिव्यक्ति 'दुकान', 'प्रतिष्ठान' या 'वाणिज्यिकप्रतिष्ठान'
किसीउपक्रमजैसेउपक्रमकोकवरकरेगीयानहीं

मैंविजलीबोर्ड. लेकिनइसअधिनियमकेप्रावधानोंकेकार्यान्वयनसेएसेउपक्रमकोबाहरकरके,
विधायिकाकातात्पर्ययहैकियद्यपिये 'दुकान', 'प्रतिष्ठान' यावाणिज्यिकप्रतिष्ठान' कीपरिभाषामेंआसकतेहैं,
फिरभीअधिनियमकेप्रावधानलागूनहींहोंगे।उसीपरलागूनहींहोगा। स्थापनाअधिनियमकीधारा 3
कायहअर्थनहींलगायाजासकताकिविधायिकानेयहपरिकल्पनाकीथीकिये 'दुकान' या 'प्रतिष्ठान' या 'वाणिज्यिकप्रतिष्ठान'
नहींहैं।वास्तवमें, इसकामतलबकेवलइतनाथाकिस्थापनाअधिनियमकेविनियामकऔरअन्यप्रावधानऐसी 'दुकान', 'प्रतिष्ठान'
या 'वाणिज्यिकप्रतिष्ठान' कोनियंत्रितनहींकरेंगेजैसाकिस्थापनाअधिनियमकीधारा 3 द्वारापहचानागयाहै।इसलिए,
यहमानाजाताहैकिधारा 1(3)(बी) केप्रावधानोंकेआधारपरग्रेच्युटीभुगतानअधिनियम, 1972
केप्रावधानस्पष्टरूपसेहरियाणाराज्यविजलीबोर्डपरलागूहोतेहैं। (पैरा 4, 5 और 6)।

भारतकेसंविधानकेअनुच्छेद 226 और 227 केतहतयाचिकामेंप्रार्थनाकीगईहैकिमामलेकेरिकार्डमांगेजाएंऔर;

(ए) आदेशपरिशिष्ट 'पी-5', दिनांक 7 नवंबर, 1975 कोरद्दकियाजाए।

(बी) किउत्तरदाताओंकोमामलेकोआगेबढ़ानेसेरोकाजाए, ताकिउत्तरदाताओं 2, 3 और 4
द्वारादावाकीजारहीग्रेच्युटीकीमात्रानिर्धारितकीजासके।

आगेप्रार्थनाकीजारहीहैकिइसयाचिकाकानिर्णयहोनेतकप्रतिवादीनंबर 1 केसमध्यलंबितआगेकीकार्यवाहीपररोकलगादीजाए।

यहभीप्रार्थनाकीजारहीहैकिअनुलग्नकोंकीप्रमाणितप्रतियोंकाउत्पादनबंदकरदियाजाए।

याचिकाकर्ताकीओरसेभागीरथदास, वरिष्ठअधिवक्ता, रमेशकुमार, उनकेसाथअधिवक्ताथे।

डी. एस. बाली, अधिवक्ता, संख्या 2 से 4 केलिए।

प्रलय

डी. एस. तेवतिया, जे.-(मौखिक)।

(1) हरियाणास्टेटइलेक्ट्रिसिटीबोर्डनेनियंत्रणप्राधिकारीऔरउपश्रमआयुक्त, हरियाणाकेआदेशकोखारिजकरदियाहै,
जिसमेंकहागयाहैकिग्रेच्युटीभुगतानअधिनियम, 1972 (इसकेबादइसे 'ग्रेच्युटीअधिनियम' कहाजाएगा) केप्रावधानथे।

यहांयाचिकाकर्ता, यानीहरियाणाराज्यपरलागूहोताहै

विद्युतबोर्डऔर, इसलिए, उत्तरदाताक्रमांक 2, 3 और 4

हरियाणाराज्यविद्युतबोर्डवनामनियंत्रणप्राधिकारीएवंउप

श्रमआयुक्त, हरियाणाएवंअन्य (डी. एस. तेवतिया, जे.)

ग्रेच्युटीके भुगतान के हकदारथे; अन्यबातों के साथ-साथ इस आधार पर किंग्रेच्युटी अधिनियम के प्रावधानों में याचिकाकर्ता - हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड (इसके बाद 'बोर्ड' कहा जाएगा) शामिल नहीं है और इसलिए, इसके कर्मचारी अपनी सेवा निवृत्ति पर किसी भी ग्रेच्युटी के हकदार नहीं थे।

(2)

याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री भागीरथ दास ने उपरोक्त रुखदोहरा याहै और बिंदु के विस्तार के माध्यम से उन्होंने आग्रह किया है कि ग्रेच्युटी अधिनियम की धारा 1 उप-धारा (3) खंड (बी) की परिकल्पना की गई है अधिनियम का लागू होना, अन्यबातों के साथ-साथ, दुकानों और प्रतिष्ठानों के संबंध में तत्समय लागू किसी भी कानून के अर्थ के अंतर्गत प्रत्येक दुकान या प्रतिष्ठान पर लागू होना। दुकानों और प्रतिष्ठानों से संबंधित एक मात्र प्रासंगिक कानून पंजाब दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम है; 1958 (इसके बाद इसे 'प्रतिष्ठान अधिनियम' कहा जाएगा); धारा 3 स्पष्ट रूप से उक्त अधिनियम के आवेदन से अन्यबातों के साथ-साथ उस उपक्रम को बाहर करती है जो जनता को विजलीय या प्रकाश की आपूर्ति करता है और इसलिए, याचिकाकर्ता विजली बोर्ड को किसी भी कानून के अर्थ में एक दुकान या प्रतिष्ठान के रूप में नहीं माना जासकता है। किसी दुकान या प्रतिष्ठान पर ग्रेच्युटी अधिनियम लागू करने की आवश्यकता।

(3) याचिकाकर्ता की ओर से दिए गए उपर्युक्त विवाद की जांच करने से पहले, दोनों कानूनों के प्रासंगिक प्रावधान सब से पहले देख्यान देने योग्य हैं: -

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972.

1' *** *

(3) यह लागू होगा-

(ए) प्रत्येक कारखाना, खदान, तेल क्षेत्र, वागान, बंदरगाह और रेलवे कंपनी।

(बी) किसी राज्य में दुकानों और प्रतिष्ठानों के संबंध में उस समय लागू किसी भी कानून के अर्थ के अंतर्गत प्रत्येक दुकान या प्रतिष्ठान, जिस में पिछले किसी भी दिन दस या अधिक व्यक्ति का र्यारत हैं, यानियोजित थे। बारह महीने।

*** *

आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

पंजाबदुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958।

2. परिभाषाएँ;

** • *

(iv) "वाणिज्यिक प्रतिष्ठान" का अर्थ है कोई भी परिसर जहां लाभ के लिए कोई व्यवसाय, व्यापार या पेशाचलाया जाता है और इस में पत्रकारिता या मुद्रण प्रतिष्ठान और परिसर शामिल हैं जिसमें बैंकिंग, बीमा, स्टॉक और शेयर, ब्रोकरेज और उत्पाद विनियमय का व्यवसाय किया जाता है। याजिस का उपयोग गद्धात्रा वास, रेस्तरां और डिंग या भोजनालय, थिएटर, सिनेमायासार्वजनिक मनोरंजन के अन्य स्थान या किसी अन्य स्थान के रूप में किया जाता है, जिसे सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान घोषित कर सकती है। इस अधिनियम के उद्देश्य.

*** ♦ ***

(viii) "प्रतिष्ठान" का अर्थ एक दुकान या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान है;

"***"

(xxv) "दुकान"

का अर्थ है कोई भी परिसर जहां कोई व्यापार से व्यवसाय किया जाता है या जहां ग्राहकों को सेवा एं प्रदान की जाती हैं और इस में कार्यालय, स्टोर-रूम, गोदाम, बिक्री-डिपोयां गोदाम शामिल हैं, चाहे उसी पूर्व में हों ऐसे व्यापार या व्यवसाय के संबंध में उपयोग किए जाने वाले या अन्यथा, लेकिन इस में वाणिज्यिक प्रतिष्ठान या किसी कारखाने से जुड़ी दुकान शामिल नहीं है, जहां दुकान में कार्यरत व्यक्तियों को 'कारखाना अधिनियम, 1948' के तहत श्रमिकों के लिए प्रदान किए गए लाभ की अनुमति है।

3. अधिनियम कुछ प्रतिष्ठानों और व्यक्तियों पर लागू नहीं: -

(ए) * * *

(बी) कोई रेलवे सेवा, जल परिवहन सेवा, ट्रामवे, डाक तारयाटेली फोन सेवा, सार्वजनिक संरक्षण या स्वच्छता की कोई प्रणाली या कोई उद्योग व्यवसाय या उपक्रम जो जनता को बिजली, प्रकाश या पानी की आपूर्ति करता है।

(4) मेरी राय में, स्थापना अधिनियम की धारा 3 इस तथ्य के बारे में अनिश्चितता को दूर करती है किंवा कोई उपक्रम

सरूपचंद और अन्य बनाम सतीश कुमार और अन्य (जे. वी. गुप्ता, जे.)

जो जनता को विजलीया प्रकाश की आपूर्ति करता है वह एक 'प्रतिष्ठान' है यानि हीं है। यदि स्थापना अधिनियम की धारा 3 नहीं होती, तो इस में परिभाषित परिभाषा खंड की व्याख्या शामिल होती है कि यह किया जासके किक्या अभिव्यक्ति 'दुकान' 3 'प्रतिष्ठान' या 'वाणिज्यिक प्रतिष्ठान', जैसा कि परिभाषित है, #

मैं याचिका कर्ता की तरह एक उपक्रम को कवर करता हूँ। लेकिन इस अधिनियम के प्रावधानों के आवेदन से ऐसे उपक्रम को बाहर करके, विधायिका कातात्पर्य यह है कि यदि पिये 'दुकान' 'प्रतिष्ठान' या 'वाणिज्यिक प्रतिष्ठान' की परिभाषा के अंतर्गत आसकते हैं, फिर भी अधिनियम के प्रावधान नहीं होंगे उसी परलागू है।

(5) मेरी राय में स्थापना अधिनियम की धारा 3 का यह अर्थ नहीं लगाया जासकता है कि विधायिका ने परिकल्पना की थी कि ये 'दुकान' या 'प्रतिष्ठान' या 'वाणिज्यिक प्रतिष्ठान' नहीं हैं। वास्तव में, इस कामतलब के बल इतना था कि स्थापना अधिनियम के विनियामक और अन्य प्रावधान ऐसी 'दुकान', 'प्रतिष्ठान' या 'वाणिज्यिक प्रतिष्ठान' को नियंत्रित नहीं करेंगे जैसा कि स्थापना अधिनियम की धारा 3 द्वारा पहचाना गया है।

(6) उपर्युक्त कारणों से मेरा मानना है कि धारा 3 (बी)

के प्रावधानों के आधार पर ग्रेच्युटी अधिनियम के प्रावधान स्पष्ट रूप से याचिका कर्ता-बोर्ड परलागू होते हैं। उपरोक्त के आलोक में, मेरा मानना है कि विवादित आदेश कानूनी है और इस याचिका में कोई योग्यता नहीं है और इसे खारिज कर दिया गया है, लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश नहीं दिया गया है।

एन.के.एस.

जे. वी. गुप्ता से पहले, जे.

सरूपचंद और अन्य, अपील कर्ता,

बनाम

सतीश कुमार एवं अन्य, प्रतिवादी।

1974 की नियमित द्वितीय अपील संख्या 1830।

17 फरवरी 1983।

पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिवंध अधिनियम (1949 का III) - धारा 13 -

एक वैधानिक किरायेदार के उत्तराधिकारी जो अपने जीवन काल के दौरान अलगरहरहे थे - वैधानिक किरायेदार की मृत्यु -

ऐसे उत्तराधिकारी -

क्या मृत्यु के बाद समाप्त परिसर पर क्षाकरने के अधिकार का दावा कर सकते हैं कि किरायेदार का केवल उत्तराधिकारी होने के आधार पर।

स्थानीय : भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है तांकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अर्शवीर कौर संधू
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
हरियाणा